through cross-breeding with high quality frozen semen of exotic breed, e.g. Jersey, Holstein-Friesian.

8. *Purchase of bulls from co-operative Societies:*

Selected bulls are purchased by the Government for distribution for breeding purposes in other villages through Veterinary hospitals and dispensaries.

9. *Feed and Fodder Development Scheme:*

Under this scheme introduction of improved Fodder crops and grassland improvement is being undertaken.

(B) *Dairy Development Projects:*

Under the operation Flood Programme, which covers the districts of Sabarkantha, Baroda, Kaira, Ahmedabad, Mehsana and Banaskantha, two milk products factories at Anand and Mehsana were expanded and two new products factories at Sabarkantha and Banaskantha were established, increasing the total capacity to 6.50 lak litres of milk per day. The other schemes being taken up under the Fifth Five Year Plan under dairy development are as follows:

1. Financial assistance to District Cooperative Milk Producers' Unions and Feeder Societies.

2. Financial assistance to consumer coop. Societies.

3. Banni Development Scheme.

4. Federation of District Cooperative Milk Producers' Union.

5. Share capital contribution to Gujarat Dairy Development Corporation.

6. Loans for Gujarat Dairy Development Corporation.

7. Development of Dairy Science College at Anand.

8. Technicians Training Centre (Grant-in-aid to National Dairy Development Board, Anand).

सिर पर मल ढोने की परिपाटी समाप्त करना

730. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री सिर पर मल ढोने की परिपाटी के बारे में 15 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 82 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रधान मंत्री को फरवरी, 1976 में प्रस्तुत ज्ञापन के उत्तर में सरकार ने सब राज्य सरकारों को सिर पर मल ढोने की परिपाटी समाप्त करने के निदेश दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने का है ; और

(ग) प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन में अन्य क्या मांगे की गई थीं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें तथा इस घृणित परिपाटी को यथाशीघ्र खत्म करने के लिए एक व्यवहार्य योजना भेजे । उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि इस परिपाटी को उपयुक्त कानून द्वारा खत्म करने के प्रश्न पर वे विचार करें । नगरीय अपशिष्ट पर गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों के अनुसार हाल ही में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सिंगापुर के माडल पर मल-सेवा के लिये पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करे । सिंगापुर माडल की मुख्य मुख्य विशेषतायें विवरण में दी गई हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 20 हजार से 50 हजार की जनसंख्या वाले एक अथवा दो उपनगरों में शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के लिए एक पायलेट योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य प्रशासनों को परिचालित की है । केन्द्रीय सरकार चुनिन्दा उप-नगरों में सीवर के पाइप बिछाने, सीवर से सम्बद्ध संरचनाओं के निर्माण तथा पूर्ति कुण्ड आदि के निर्माणार्थ इस योजना के लिये पूर्ण अनुदान सहायता दे रही है । पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिये 2.30 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(ग) अभ्यावेदन में दिखाई गई अन्य मुख्य-मुख्य मांगे ये है :—

(1) आधुनिक सुख-सुविधाओं सहित मकान तथा मालकाना हकूक देना ,

(2) ऐसे कर्मचारियों को सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर समझना ।

ये मामले पूर्णतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते है ।

विवरण

सिंगापुर माडल पर मल-सेवा पर पायलट परियोजनाओं के लिए प्राचल ।

(1) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये शहरों में एकत्र किए गए मल के निपटान करने हेतु आंशिक मल-निर्यास प्रणाली अवश्य होनी चाहिये ।

(2) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले शहर मे क्षेत्रफल ऐसा होगा कि उस क्षेत्रफल में किसी भी अवस्था में अगले दस वर्षों में मल-नालियों की व्यवस्था नहीं की जाएगी

(3) चूंकि इस योजना के आरम्भ करने से शुष्क शौचालयों के वर्तमान प्रकारों में संरचनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक हो जाएगा अत. लोक शिक्षा का एक जोरदार अभियान आरम्भ करना चाहिये ।

(4) राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को रोज बदलने के लिए प्रति मकान दो डोल के हिसाब से मानक आकार के डोल क्षेत्र के निवासियों के लिए प्राप्त करने तथा उन्हें देने चाहिये ।

(5) राज्य सरकार /स्थानीय निकाय को डोलों को ले जाने के लिए उपयुक्त डिजाइन के वाहन देने चाहिये ।

(6) चूंकि योजना को आरम्भ करने से मल को सिर पर ले जाना समाप्त नही होगा । अत कार्मिकों को दस्ताने आदि जैसी स्वास्थ्य-सुविधाये दी जानी चाहिये ।

(7) चुनी हुई जगहों पर डोलों का मल मल-प्रणाली में बहा देने तथा डोलों को साफ करने और रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए डिपुओं का निर्माण करना चाहिये ।

(8) डिपो के स्थलों पर दबाव सहित पर्याप्त जल सप्लाई उपलब्ध करना बहुत महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है ।

(9) इन डिपुओं के निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन में स्वास्थ्य सम्बन्धी मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये ।

(10) उन स्थानों में जहां अलग-अलग रिहायशों में वाहन नहीं जा सकते हैं वहां उपयुक्त रूप से निर्मित एक पहिये वाली रेढ़ियां उपलब्ध की जानी चाहियें जिससे कार्मिक अधिक संख्या में डोलों को वाहनों तक ले जा सकें ।

(11) डोलों के उपयुक्त अनुरक्षण तथा उनसे कुछ गिरे बिना उनके ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त पर्यवेक्षण होना चाहिये ।

Report on Muslim Waqf

732. DR. RANEN SEN:
SHRI ISHAQUE SAMBHALI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Late Prof. Humayun Kabir had submitted a report on Muslim Waqf;

(b) if so, the main recommendations put forward by him;

(c) whether Government have implemented any of these recommendations; and

(d if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Co-operative Societies in Tribal Blocks in Kerala

733. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have set up co-operative societies in the tribal blocks in Kerala State;

(b) if so, the salient features of the functioning of these societies; and

(c) facilities provided so far to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the co-operative societies in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) Yes.

(b) Most of the Societies are Multipurpose Cooperative Societies and their functions inter alia are:—

1. Distribution of Agricultural loans and consumption loans to Members.

2. Distribution of Agricultural inputs.

3. Marketing of Agricultural produce and minor forest produce.

4. Distribution of Essential commodities to Members.

5. Under taking minor forest contract works etc.

(c) The Co-operative Societies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes provide the following facilities to their members:—

1. Lending of Agricultural loans and consumption loans of Members.

2. Distribution of Agricultural inputs to Members.

3. Organising Cooperative Farms.

4. Marketing of Agricultural produce and minor forest produce of Members.

5. Distribution of essential commodities to Members etc.

Besides these, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are eligible for